



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 95]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 20, 1984/आषाढ 29, 1906

No. 95]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 20, 1984/ASADHA 29, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

बाणिज्य मंत्रालय

नई दिल्ली, 20 जुलाई, 1984

संकल्प

सं० 2 (51)/84-ईपीएल :- अर्थ व्यवस्था में विदेशी व्यापार के सामरिक महत्व को ध्यान में रखते हुए सरकार ने निर्यातों और आयातों के क्षेत्र में इनकी स्थिति की पुनरीक्षा करने के लिए बाणिज्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति बनाने का निर्णय किया है। समिति का कार्य देश की आर्थिक स्थिति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को ध्यान में रखते हुए निर्यात संवर्धन के उपायों और आयात नीतियों के प्रभाव का विश्लेषण करने और इसके साथ-साथ जहाँ कहीं आवश्यक हो उसे युक्ति युक्त बनाने और उसमें सुधार करने के लिए सुझाव देना होगा। समिति की रिपोर्ट अल्प कालिक एवं दीर्घ कालिक नीति बनाने के लिए एक आधार प्रदान करेगी जिसमें कि हमारी अर्थ व्यवस्था के विकास की प्राथमिकताओं के अनुसार हमारे निर्यातों को शीघ्रता से बढ़ाने के लिए और आयातों की युक्ति युक्त बनाने के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। समिति का गठन इस प्रकार होगा :-

1. श्री आशिष हुसैन
बाणिज्य सचिव

अध्यक्ष

2. श्री पी० के० कोल
वित्त सचिव

सदस्य

3. श्री एस. एस. सिद्धू
सचिव, औद्योगिक विकास

सदस्य

4. श्री भर्जुन सेन गुप्ता
प्रधान मंत्री के विशेष सचिव

सदस्य

5. डाक्टर सी रंगाराजन
डिप्टी गवर्नर
भारतीय रिजर्व बैंक

सदस्य

6. श्री एम. नरसिम्ह,
प्राचार्य
भारतीय प्रशासनिक स्टाफ कालेज,
हैदराबाद।

सदस्य

7. श्री पी.सी. जैन,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

सदस्य

8. डा. दीपक नायर,
आर्थिक सलाहकार,
बाणिज्य मंत्रालय।

सदस्य सचिव

2. कमेटी के बिबाराय विषय की शर्तें निम्नलिखित होंगी :-

(1) आयात और निर्यात नीति के वर्तमान ढाँचे की पुनरीक्षा करना,

- (2) निर्यात संबंधित उपायों के प्रभावों को वास्तविक निर्यात निष्पादन उनके प्रभाव की जाँच करना,
 - (3) जहाँ कहीं आवश्यक हो निर्यात नीतियों में सुक्ति युक्त बनाने और उसमें सुधार लाने के लिए सुझाव देना और
 - (4) विदेशी मुद्रा का संरक्षण करने और निपुण आयात प्रतिस्थापन को बढ़ावा देने के लिए आयात नीतियों में परिवर्तन लाने और उन्हें सुकियुक्त बनाने के लिए सुझाव देना।
3. समिति यदि आवश्यक समझे तो उपर्युक्त विचारार्थ धिसों की शर्तों से संबंधित किसी अन्य पहलु पर भी विचार कर सकती है।
4. समिति यदि आवश्यक समझे तो अपने कार्य के किसी विशेष क्षेत्र के लिए सलाहकारों को रखने सहित कार्य की प्रवर्तन स्वयं की प्रवृत्ति तैयार करेगी।
5. समिति को सदस्यों की अगुआई के मातहत अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।
6. समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा।

(टो. एस० आर० सुब्रमनियम) संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE

New Delhi, the 20th July, 1984.

RESOLUTION

No. 2(51)/84-EPL.—In view of the strategic importance of foreign trade in the economy, the Government have decided to appoint a high-level Committee, under the Chairmanship of the Commerce Secretary, to review the situation in the sphere of exports and imports. The task of the Committee would be to analyse the effectiveness of export promotion measures and import policies as well as to suggest rationalisation and improvements, wherever required, keeping in view the domestic economic situation as also the international context. The Report of the Committee would provide a base for policy formulation in the medium-term and long-term, in order to attain the objectives of accelerating growth in our exports and rationalising our imports, in a manner consistent with the development priorities of the economy. The constitution of the Committee shall be as follows:—

- | | |
|---|----------|
| 1. Shri Abid Hussain
Commce Secretary. | Chairman |
| 2. Shri P.K. Kaul,
Finance Secretary. | Member |
| 3. Shri S.S. Sidhu,
Secretary, Industrial Development. | Member |

- | | |
|---|------------------|
| 4. Dr. Arjun Sengupta,
Special Secretary to
Prime Minister. | Member |
| 5. Dr. C. Rangarajan,
Deputy Governor
Reserve Bank of India. | Member |
| 6. Shri M. Narasimham,
Principal,

Administrative Staff
College of India,
Hyderabad. | Member |
| 7. Shri P.C. Jain,
Chief Controller of Imports and Exports | Member |
| 8. Dr. Deepak Nayyar,
Economic Adviser,
Ministry of Commerce | Member-Secretary |

2. The terms of reference of the Committee will be as follows:—

- (i) To review the present structure of export and import policies;
- (ii) to examine the effectiveness of export promotion measures in terms of their impact on actual export performance;
- (iii) to suggest rationalisation and improvements, wherever necessary, in export policies; and
- (iv) to suggest appropriate changes and rationalisation of import policies for the conservation of foreign exchange and the promotion of efficient import substitution.

3. The Committee may, if necessary, consider any other aspect related to the above terms of reference.

4. The Committee will formulate its own procedure of work including engagement of consultant(s), if considered necessary, for any specific area of its work.

5. The Committee will submit its report within a period of six months.

6. The Headquarters of the Committee will be at New Delhi.

T.S.R. SUBRAMANIAN, Jt. Secy.